आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA PMMSY

नीली क्रांति के साथ अर्थ क्रांति

मत्स्यिकी क्षेत्र में परिवर्तन

9 भारतीय मत्स्यिकी क्षेत्र की वर्षों की उपलब्धियाँ

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

Azadi Ka Amrit Mahotsav

DEPARTMENT OF FISHERIES
Government of India

G20 भारत 2023 INDIA

मछुआरों और मत्स्य किसानों के जीवन में परिवर्तनकारी

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

20,050 करोड़ रु/- का निवेश

47.19 लाख रोजगार के अवसर सृजित

सहायता प्रदान की गई प्रमुख गतिविधियां

- मछुआ बंधुओं के लिए मछली पकड़ने की नई नावें और जाल
- मत्स्यन गतिविधि पर वार्षिक प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता
- मत्स्यन बन्दरगाह और मत्स्य उतराई केन्द्रों को आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकास
- कोल्ड चेन सुविधाएं और आधुनिक मत्स्य बाजार
- उच्च आय के लिए सी केज कल्टीवेशन, सी वीड कल्टीवेशन और सजावटी मत्स्य पालन
- आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पुन: बहाली
- मछुआ बंधुओं की सुरक्षा के लिए निगरानी, नियंत्रण और संचार प्रणाली

"हमारी सरकार हमारे मछुआ बंधुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जिसमें ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना, अवसंरचना को उन्नत करना और इसी प्रकार के बहुत सारे कार्य शामिल हैं ।''

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री

विषयवस्तु

1.	परिचय	01
2.	पिछले 9 वर्षों में सरकार की नीतियाँ और पहल	02
3.	मत्स्यिकी क्षेत्र में अब तक का सर्वोच्च निवेश	03
4.	मुख्य उपलब्धियाँ	04-06
5.	नीली क्रान्ति योजना	07
6.	मत्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना निधि (एफआईडीएफ)	08
7.	प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	09
8.	पीएमएमएसवाई : मत्स्यिकी क्षेत्र में परिवर्तन की गाथा	10
9.	मुख्य सुधार और पीएमएमएसवाई के तहत पहल	11
10.	प्रौद्योगिकी का समावेशन	12-14
11.	वैकल्पिक टिकाऊ आजीविका	15
12.	भूमि एवं जल का उत्पादक उपयोग	16
13.	उद्यमिता मॉडल	17
14.	रोजगार सृजन और आजीविका सहायता	19
15.	निर्यात दोगुना	20
16.	मत्स्यिकी क्षेत्र में आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर	21-22
17.	पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रत्याशित परिणाम और लाभ	23
18.	केसीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन	25-28
19.	परियोजनाएं और पहल को वास्तविक मूर्त रूप देना	29
20.	पीएमएमएसवाई : उपलब्धियां (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23)	29
21.	नई पहली	36
22.	आउटरीच गतिविधियां	41
23.	समाचारों में	44

परिचय

भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य पोषण सुरक्षा के साथ–साथ रोजगार सृजन में योगदान देता है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को और मूल्य श्रृंखला से जुड़े कई लोगों को आजीविका प्रदान करता है

भारत समृद्ध और विविध मात्स्यिकी संसाधनों से समृद्ध है और विविध प्रकार की मत्स्य प्रजातियों का उत्पादन करता है, इसलिए इसे ''सूर्योदय क्षेत्र'' के रूप में पहचाने जाने के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। पिछले नौ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर और मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में पहचाना जाता है।

अतः सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में प्रजातियों के विविधीकरण, सर्वोत्तम जल कृषि प्रथाओं, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए सभी स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर ग्राउंड करे ।

पिछले 9 वर्षों में सरकारी पहल और नीतियां

2015-16	कुल 5,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नीली क्रांति योजना शुरू की गई
2017-18	राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति लॉन्च की गई
2018-19	मात्स्यिकी और जल .षि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) 7,522 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ लॉन्च किया गया
2018-19	मछुआरों के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार,
2018-19	मत्स्यपालन के लिए विशेष विभाग बनाया गया
2019-20	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का अलग मंत्रालय बनाया गया
2020-21	20,050 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई

मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश

विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों अर्थात **नीली क्रांति, मात्स्यिकी और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ), प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)** और केंद्रीय बजट 2023–24 के दौरान घोषित पीएमएमएसवाई के अंतर्गत नई उप योजना के तहत मात्स्यिकी क्षेत्र में **38,572 करोड़ रुपये का निवेश**

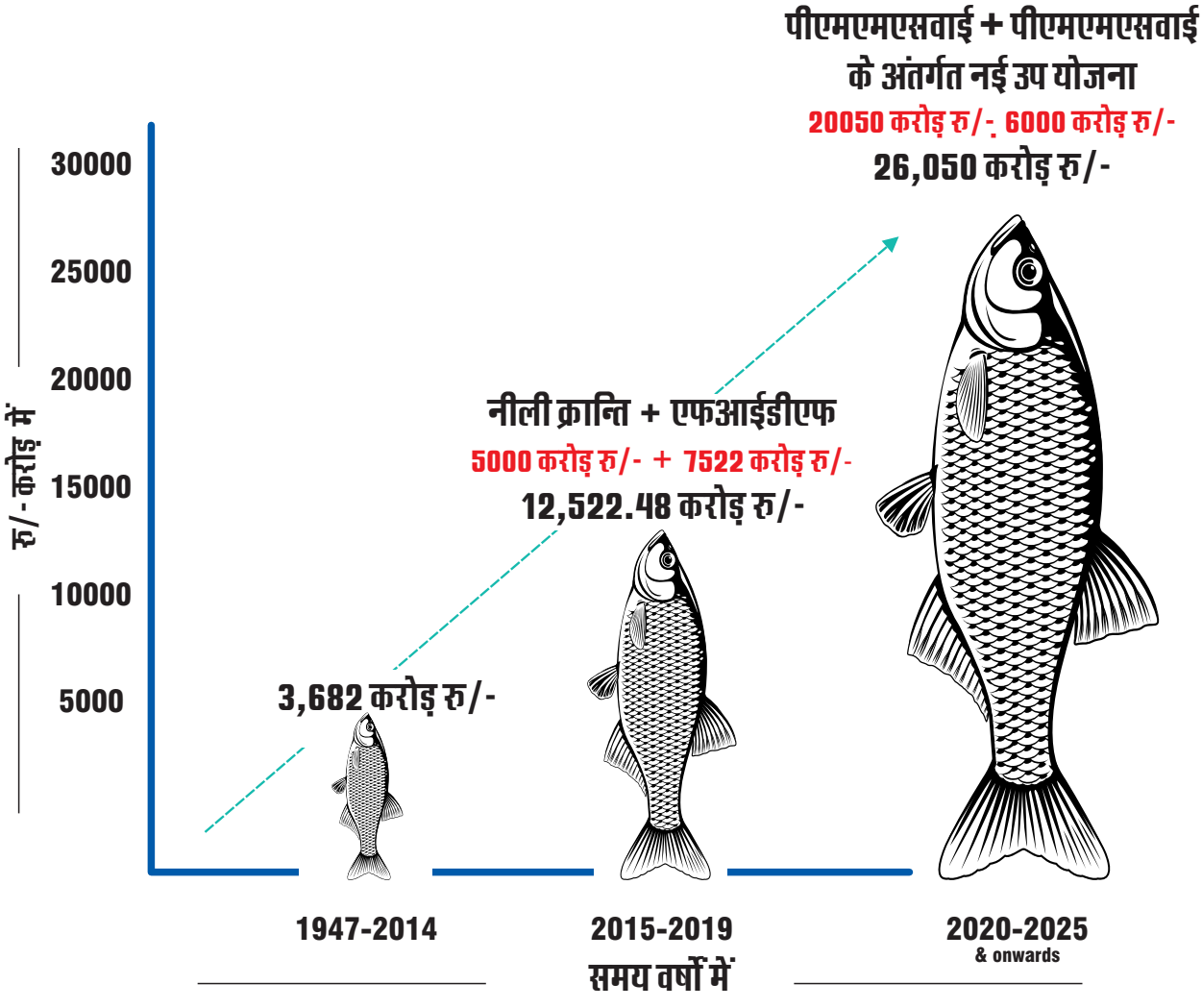

वित्त वर्ष 2020–21, वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत **14,654.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से परियोजनाएं** स्वीकृत। परिकल्पित निवेश का 73% हासिल किया गया ।

उपलब्धियां

रेकॉर्ड मत्स्य उत्पादन

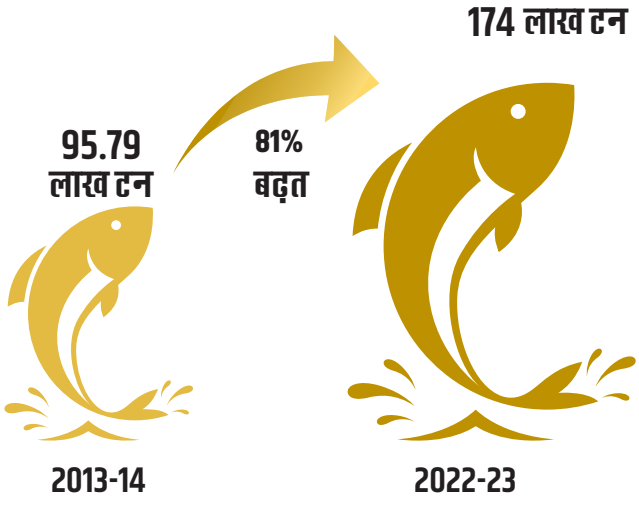

1950 के बाद से और 2022–23 में **राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में 22 गुना वृद्धि**

अंतर्देशीय और जल कृषि उत्पादन में दोगुना वृद्धि

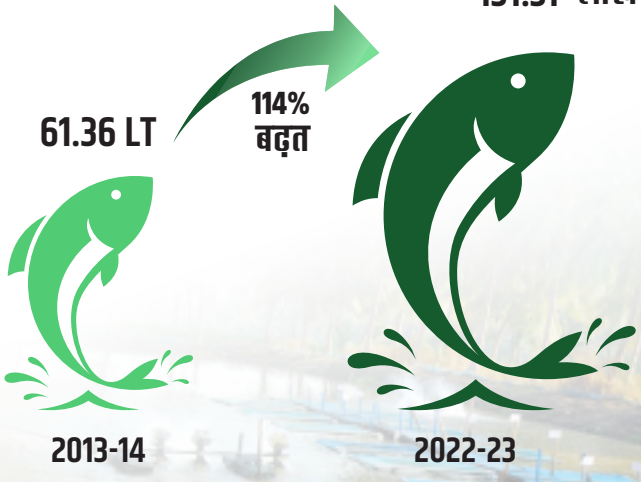

- भारत दुनिया का **सबसे बड़ा अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादक देश है**
- 2014–15 से 2022–23 के दौरान **61.36 लाख टन अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि उत्पादन हासिल किया**

रिकॉर्ड मत्स्य उत्पादन मछुआरों, मत्स्य किसानों तथा मात्स्यिकी और जल .षि क्षेत्र के उद्यमियों की बढ़ी हुई आय का संकेत देता है । यह मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों की बढ़ती रुचि को भी दर्शाता है ।

समुद्री खाद्य निर्यात को दोगुना करना

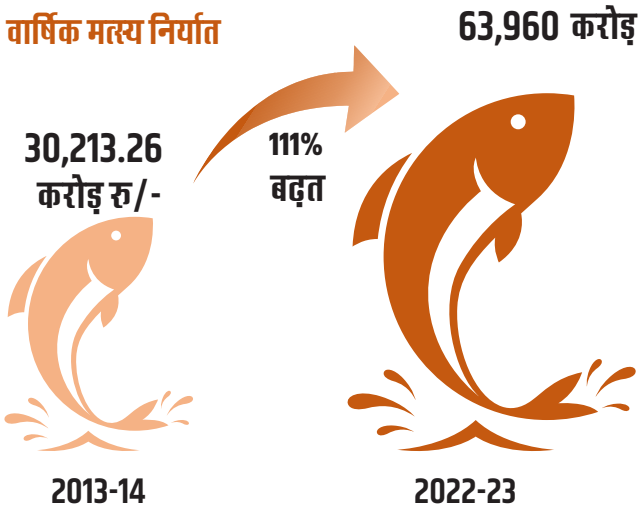

- भारतीय समुद्री खाद्य 129 देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा आयातक यूएसए है
- संचयी निर्यात 2005–06 से 2013–14 तक 1.20 लाख करोड़ रु/–था जबकि 2014–15 से 2022–23 तक 3.41 लाख करोड़ रुपये रहा।

खारे पानी में जल कृषि उत्पादन दोगुना हुआ

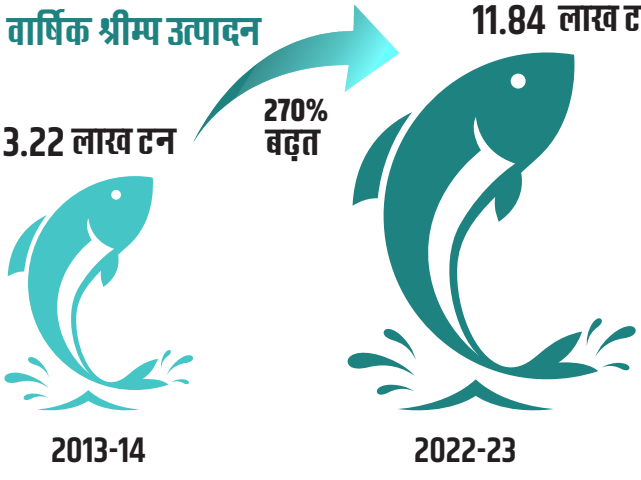

- खारे पानी की जल कृषि हजारों विविध छोटे जलीय कृषि किसानों की सफलता की कहानी है और इस सफलता में श्रीम्प कल्टिवेशन ने अग्रणी भूमिका निभाई है

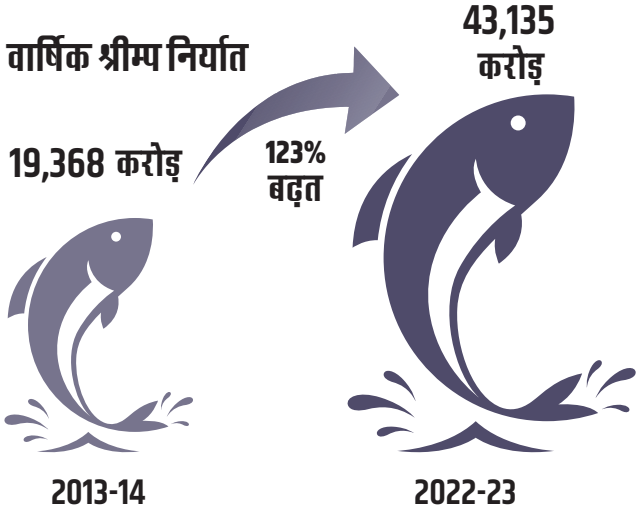

सफलता की कहानी

श्री सुभाष दास, असम फिन फिश हचेरी

हाईस्कूल स्नातक श्री सुभाष दास अब एक प्रगतिशील मत्स्यकिसान हैं और अपने क्षेत्र में एक आदर्श हैं। उन्होंने मत्स्य और मत्स्य बीज पालन का एक सफल व्यवसाय स्थापित किया है और अपनी घरेलू आय में 90% से अधिक की वृद्धि की है और अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया है। 2021–22 में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर जिले में मत्स्य पालन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें जिले में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य किसान का पुरस्कार दिया गया।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
कछार, असम	पीएमएमएसवाई, 2020-21, फिन फिश हैचरी के निर्माण के लिए 10 लाख रु/-

परियोजना की मुख्य बातें (2020-21)

- छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन के साथ आईएमसी, चाइनीज कार्प और माइनर कार्प का प्रजनन और बीज उत्पादन
- परिचालन लागतः मत्स्य पालन और हैचरी के लिए 1.5 से 2 लाख रु./हेक्टेयर
- वार्षिक रूप से 1 से 4 हार्वेस्ट
- वार्षिक गुणवत्ता वाली मत्स्य बीज उत्पादनः 19.2 मिलियन फ्राई (60 मिलियन स्पॉन)
- वार्षिक मत्स्य उत्पादनः 14 मीट्रिक टन
- 5 मिलियन मत्स्य बीज आसपास के जिलों और मिजोरम को निर्यात किए गए, 15 मिलियन बीज बेचे गए
- 5 स्थानीय युवाओं को रोजगार

आय में वृद्धि

वार्षिक आय **24 लाख** तक

कुल आय **12 लाख**

नीली क्रांति योजना परिवर्तन की लहर

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं, मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की सामाजिक–आर्थिक भलाई सुनिश्चित करते हुए मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित और समग्र विकास पर जोर दिया है।

नीली क्रांति योजना

नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन 2015–2016 में 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ के केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मात्स्यिकी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। नीली क्रांति योजना के माध्यम से सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के सराहनीय परिणाम मिले हैं।

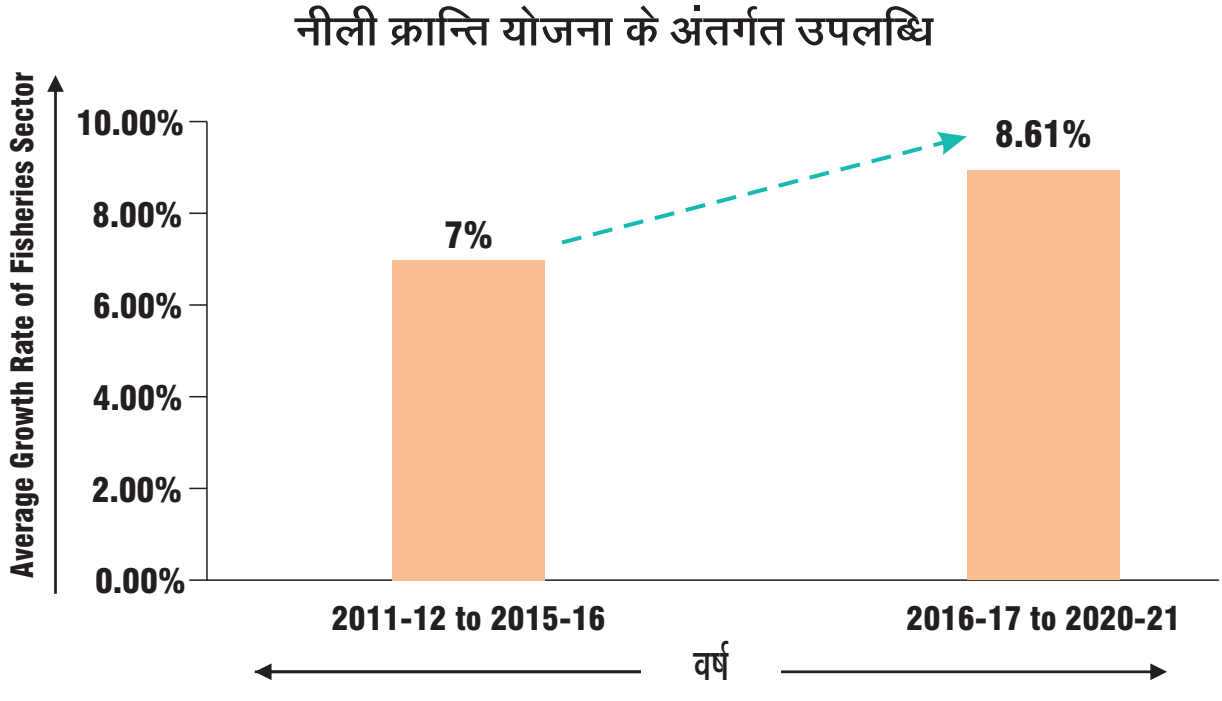

मात्सियकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मत्स्य पालन विभाग ने 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) स्थापित की ।

उद्देश्य:

- केप्चर और कल्चर के लिए तथा समुद्री और अंतर्देशीय जल कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और आधुनिकीकरण
- पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करना और घरेलू विपणन सुविधाओं में सुधार करना
- संसाधन अंतर को पाटना और चल रही इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करना

उपलब्धियां :

121 प्रस्ताव कुल परियोजना लागत

5588.63 करोड़ रुपये इंटरेस्ट सबवेंशन की पात्रता **3738.19** करोड़ रुपये

एनएलई द्वारा **3294.41** करोड़ रुपये के **91** प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

22 फिशिंग हार्बर पर **4905.77** करोड़ रुपये का निवेश

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल

24 फिश लैंडिंग सेंटर **182.20** करोड़ रुपये निवेश

तमिलनाडु और ओडिशा

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाः मात्स्यिकी क्षेत्र की कमियों पर सुधार कार्य

नीली क्रांति योजना मात्स्यिकी क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम थी। हालाँकि, मात्स्यिकी क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए और प्रयास किए जाने आवश्यक हैं ।

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi launches Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana

मूल्य श्रृंखला में मत्स्य उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण से लेकर पोस्ट–हार्वेस्ट इन्फ्राट्र्क्चर, ट्रेसेबिलिटी और मार्केट लिंकेज तक क्रिटिकल गैप्स को दूर करने के लिए क्षेत्र को सुधारों की आवश्यकता है, इसी के ध्यानार्थ, भारत सरकार ने मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मात्स्यिकी क्षेत्र को नई ऊंचाई हासिल करने में मदद करने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की कल्पना की है।

पीएमएमएसवाई : मात्स्यिकी में परिवर्तन की गाथा

नई प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक अग्रणी पहल है।

छत्तीसगढ़, बसना के निकट साहू दीपा में आरएएस

तमिल नाडु में कसमेडु हार्बर में मत्स्यन नाव

पीएमएमएसवाई केंद्र प्रायोजित नीली क्रांति योजना की सफलताओं पर आधारित है और इसका लक्ष्य मात्स्यक्की क्षेत्र को अगले स्तर पर ले जाना है। उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन जैसे मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला के साथ अपने बहु–आयामी हस्तक्षेप और गतिविधियों के साथ, पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को बदलना है और मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के लिए आर्थिक समृद्धि लाना है।

पीएमएमएसवाई के तहत मुख्य सुधार और पहल

- मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में निवेश वृद्धि
- प्रौद्योगिकी का समावेश
- नीति संबंधी सहायता
- वित्तीय समावेशन
- वैकल्पिक आजीविका और उद्यमिता
- भूमि एवं जल का उत्पादक उपयोग
- क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का विकास

प्रौद्योगिकी का समावेशन : प्रति बूंद अधिक फसल

पीएमएमएसवाई ''प्रति बूंद अधिक फसल'' हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी के समावेशन और इष्टतम जल प्रबंधन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में क्रिटिकल गैप्स को संबोधित करने पर जोर देती है।

जलीय कृषि के विस्तार, गहनता और विविधीकरण के लिए 2841 करोड़ रुपये के निवेश की योजना

तमिलनाडू के पुलिकट झील में केज

New Technologies under PMMSY

- री–सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस)
- बायो–लोक
- एक्वापोनिक्स
- उच्च घनत्व तालाब जल.षि
- इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर (आईएमटीए)
- पेन कल्चर

अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यकी में प्रौद्योगिकी का समावेशन

पीएमएमएसवाई: 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (सितम्बर 2023 तक) उपलब्धियां

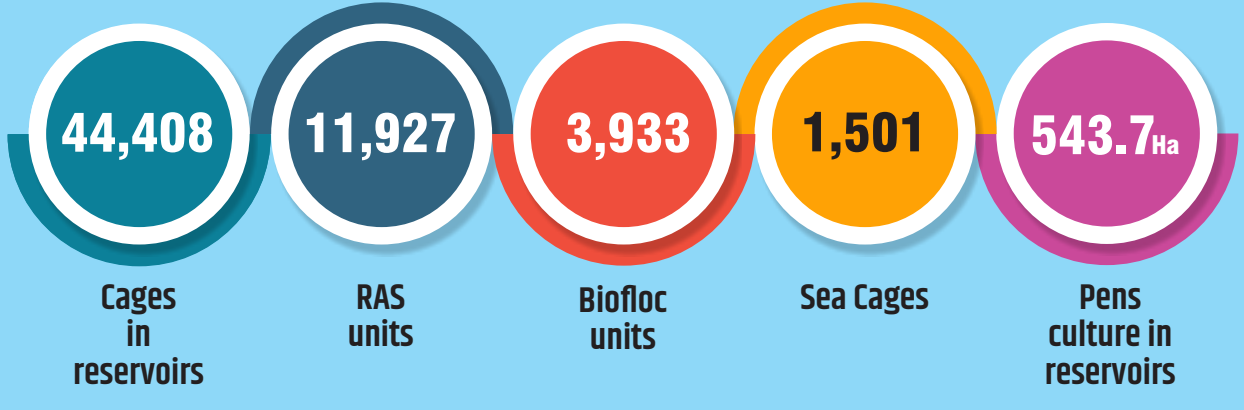

सफलता की कहानी

श्रीमती अमृता किनारे, महाराष्ट्र

श्रीमती अमृता किनारे एक प्रगतिशील मत्स्य किसान हैं, जिन्होंने मात्स्यिकी गतिविधियों के लिए अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित किया । श्रीमती किनारे ने शुरुआत में कुल घरेलू आय में योगदान देकर व्यवसाय की स्थापना की। अब उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं। उनहोंने 2 स्थायी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है, जिन्हें तकनीकी पहलुओं और मात्स्यिकी प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया है ।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
पालघर महाराष्ट्र	पीएमएमएसवाई , 2021-22, आरएएस निर्माण के लिए 15 लाख रु/-

परियोजना की मुख्य बातें

- पंगेसियस का पालन–पोषण
- वार्षिक रूप से 1 हार्वेस्ट
- वार्षिक मत्स्य उत्पादन रू 10 टन
- 2 कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित
- घरेलू खपत के लिए थोक खरीदार को मत्स्य का विपणन

आय में वृद्धि

वार्षिक आय **16.50** लाख तक

कुल आय **4.90** लाख तक

गहरे समुद्र के मत्स्यन जहाज (डीप सी फिशिंग वेससेल्स)

पारंपरिक मछुआरों के लिए उच्च आय में सहायता

जहाज का प्रकार	वार्षिक लाभ
मोटर चालित जहाज	3 लाख रु/–
यंत्रीकृत जहाज	8–10 लाख रु/–
मॉडर्न डीप–सी फिशिंग वेसेल	32 लाख रु/–

पीएमएमएसवाई: 2020-21, 2021-22 और 2022-23 और 23-24 (सितम्बर 2023 तक) के दौरान उपलब्धियां

2,255

यंत्रीकृत जहाजों में जैव–शौचालय

1143

मौजूदा मत्स्यन जहाजों का उन्नयन जहाज

463

गहरे समुद्र के

पीएमएमएसवाई 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन देती है

- मत्स्यन जहाजों का आधुनिकीकरण
- कम लागत वाली स्वदेशी मत्स्यन जहाज
- मदर वेसल्स

वैकल्पिक सतत आजीविका

- पारंपरिक मछुआरों के सुरक्षित जीवन और आजीविका के लिए मैरीक्लचर
- अगले 10 वर्षों में 25% समुद्री मछुआरे समुद्री कृषि में करने लगेंगे
- केज कल्चर और सी वीड कल्टिवेशन को बढ़ावा देना: पीएमएमएसवाई के तहत 1,276 करोड़ निवेश की योजना
- सी वीड कल्टिवेशन से तटीय मछुआरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा

सी वीड कल्टिवेशन, तमिलनाडु

सी. केज कल्टिवेशन कम जोखिम, अधिक लाभ

गतिविधि	पूंजी लागत	प्रति वर्ष कुल आय
पारंपरिक मत्स्यन जहाज	5 लाख रु/–	1.2 लाख रु/–
केज कल्टिवेशन (कोबिया)	5 लाख रु/–	1.8 लाख प्रति केज

टिकाऊ मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय पर कम प्रभाव डालने और तटीय मछुआरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रत्येक **एकीकृत मॉडल तटीय मत्स्यन गांव के विकास के लिए 7.5 करोड़ रुपये** का निवेश किया जाएगा।

पीएमएमएसवाई :- 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (सितम्बर 2023 तक) के दौरान उपलब्धियां

- **66,020** सी वीड कल्टिवेशन मोनोलीन/ट्यूबनेट प्रणाली
- **45,090** सी वीड कल्टिवेशन राट प्रणाली
- **2** एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँव

भूमि और जल का उत्पादक उपयोग : ऊषर भूमि से समृद्ध भूमि की ओर

जलीय कृषि के लिए क्षारीय और लवणीय भूमि के उत्पादक उपयोग हेतु 576 करोड़ रु/– के निवेश की योजना

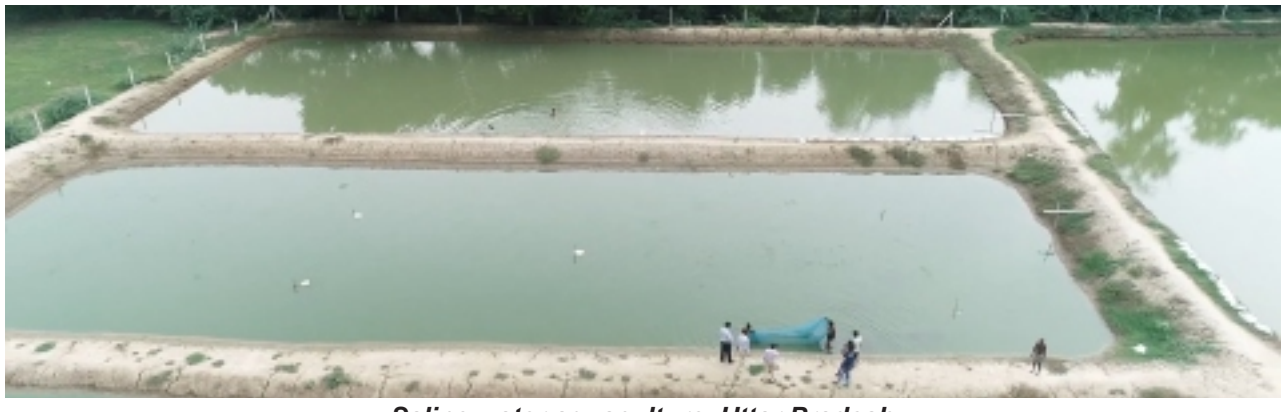

Saline water aquaculture, Uttar Pradesh

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एंड टू एंड लिंकेज के साथ एक्वा हब का विकास
- पीएमएमएसवाई के तहत 10 लक्ष केक्टेयर के जलाशय और वेटलैंड में मात्स्यिके के विसका हेक० 520 करोड़ रु/– का निवेश (वित्त वर्ष 202–25) ।

पीएमएमएसवाई : 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (सितम्बर 2023 तक) के दौरान उपलब्धियां

2855.59 हेक० क्षारीय और लवणीय जल-कृषि के लिए तालाब क्षेत्र

उद्यमिता मॉडल

पी.एम.एम.एस.वाई. का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एक अनुकूल परिवेश का सृजन करना, उद्यमिता तथा नवाचारी व्यापार मॉडल तैयार करना है

मात्सियकी और जलीय कृषि में नवाचार, स्टार्ट–अप्स, और इनक्यूबेशंस, युवाओं की सहभागिता और उद्यमिता का विकास

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में (वित्त वर्ष 2020–25) उद्यमिता विकास मॉडल के लिए 100 करोड़ रुपयें निर्धारित

मेसर्स शिल्पा हैचरीज एलएलपी / श्रीमती मांजा नाइक, विशाखापट्टनम ,
आंध्र प्रदेश–उद्यमी मॉडल 2021–22

उद्यमिता बढ़ाने हेतु युवाओं का सशक्तिकरण

- स्टार्ट अप चुनौती का आयोजन
- प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन केन्द्र का विकास
- प्रत्येक एक्वापार्क में एक मत्स्य इनक्यूबेशन सेंटर
- स्टार्ट–अप्स / एकीकृत इकाइयों के लिए पी.एम.एम. एस.वाई. के अन्तर्गत सहायता का आकर्षक पैकेज

सफलता की कहानी

श्रीमती रेशमा देवी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेशमा देवी पेशे से एक दर्जी थीं और अपने पति श्री सुभाष चंद, जो कि दिव्यांग हैं, के साथ पारंपरिक खेती करती थीं। इससे उन्हें 5,000 रु/– की नाममात्र मासिक आय सभी गतिविधियों से प्राप्त होती थी ।

उनकी उद्यमशीलता की मानसिकता ने उन्हें नई चुनौतियाँ लेने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग की मदद से विभिन्न मात्स्यिकी और जलीय कृषि गतिविधियों के बारे में सीखा।

लगातार प्रयासों से, मत्स्य पालन उनकी आय का प्राथमिक स्रोत बन गया है जिसे वह आने वाले समय में विस्तारित करने की योजना बना रही हैं।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
उना हिमाचल प्रदेश	पीएमएमएसवाई, वित्त वर्ष 2021-22, 8.40 लाख बायोलोक्क पॉण्ड के निर्माण के लिए

परियोजना की मुख्य बातें

- प्राप्त धनराशि से उन्होंने 24 सेंट में फैले बायोलॉक तालाबों का निर्माण किया, जिसमें कार्यालय कक्ष और चौकीदार की तैनाती जैसी सुविधाएं थीं।
- केसीसी से 1.5 लाख रुपये का लोन भी लिया।
- वार्षिक मत्स्य उत्पादनः 7 टन
- प्रजातियाँ – आईएमसी
- रोजगार सृजित – 3 व्यक्ति

आय में वृद्धि

वार्षिक आय
7.23 लाख

रोजगार सृजन और आजीविका सहायता

पीएमएमएसवाई समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मत्स्य पालन, इको–पर्यटन, समुद्री आधारित हस्तशिल्प, मत्स्य/अन्य समुद्री कच्चे माल के मूल्यवर्धन के माध्यम से वैकल्पिक आजीविका के निर्माण को बढ़ावा देता है।

वाहन वितरण, देहरादून, उत्तराखंड

वाहन वितरण, नयागढ़,

- 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे – 15 लाख प्रत्यक्ष मात्स्यिकी में, 40 लाख संबद्ध गतिविधियों में ।
- समुद्री और अंतर्देशीय दोनों क्षेत्रों में मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान 6.77 लाख परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी

पीएमएमएसवाई: 2020-21, 2021-22 2022-23 और 2023-24 के दौरान उपलब्धियां (सितम्बर 2023 तक)

47.19 लाख — **रोजगार अवसर सृजित**

केरल के मत्स्य किसान

निर्यात दोगुना

निर्यात दोगुनाभारत समुद्री खाद्य के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। समुद्री उत्पादों का निर्यात 1.37 एमएमटी (वित्त वर्ष 2021–22) से बढ़कर 1.74 एमएमटी (वित्त वर्ष 2022–23) हो गया । यह निर्यात मूल्य में 32% की वृद्धि दर्शाता है जो कि 63,969.14 करोड़ रूपये (यूएसडी 8.09 बिलियन) है ।

26.73% निर्यात में वृद्धि

7.11 LT कुल फ्रोजेन श्रीम्प निर्यात (2022–23)

सबसे बड़ा आयातक यूएसए, चाइना

74% स्थानीय प्रजातियों के निर्यात में वृद्धि पी मोनोडोन (मात्रा)

पीएमएमएसवाई का लक्ष्य 2025 तक मात्स्यिकी निर्यात को 46,663 करोड़ रूपये से दोगुना कर 1 लाख करोड़ रूपये करना है

- क्लस्टर, प्रजातियों के विविधीकरण, मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजीस्टिक्स सपोर्ट , विपणन और ब्रांड इंडिया के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना
- फोकस प्रजातियाँ – तिलापिया, पंगासियस, सी बैस, स्कैम्पी और मड क्रेब

एमएसएमई (भारत सरकार) द्वारा सहायता प्राप्त फालकन प्रोसेसिंग प्लांट, ओड़ीशा

मात्स्यिकी क्षेत्र में आधुनिक इनफ्रास्ट्रक्चर

मात्स्यकी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अब तक का सबसे अधिक 7,710 करोड़ का निवेश

चेन्नई फिशिंग हार्बर, तमिल नाडु

- बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों (फिश लैंडिंग सेंटेर्स) के लिए 8,000 करोड़ रु.
- कोल्ड चेन और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2400 करोड़ रु.

मूल्य श्रृंखला में संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए की जा रही महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में फिश लैंडिंग सेंटेर्स की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है ।

हेजामंडी, कर्नाटक में फिशिंग हार्बर

वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2023–24 में कुल 3490 करोड़ रुपये निवेश मत्स्यन बंदरगाहों के विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण और रखरखाव ड्रेजिंग और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए स्वीकृत ।

कुल परिकल्पित निवेश

2400 करोड़ रु/-
नए फिशिंग हार्बर (मत्स्यन बन्दरगाह) के लिए

400 करोड़ रु/-
8 फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण के लिए

625 करोड़ रु/-
25 फिश लैंडिंग सेंटेर्स के लिए

65 करोड़ रु/-
मैंटेनेंस ड्रेडजिंग के लिए में वृद्धि पी मोनोडोन (मात्रा)

2024-25 तक पीएमएमएसवाई के प्रत्याशित परिणाम और लाभ

मत्स्य उत्पादन लाख टन में

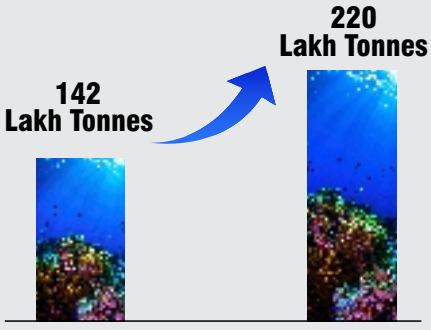

मत्स्य उत्पादन का औसत वार्षिक वृद्धि दर

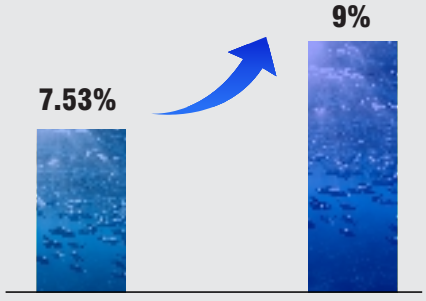

औसत जल कृषि उत्पादकता टन प्रति हेक्टेयर में

रोजगार श्रीजा (लाख में)

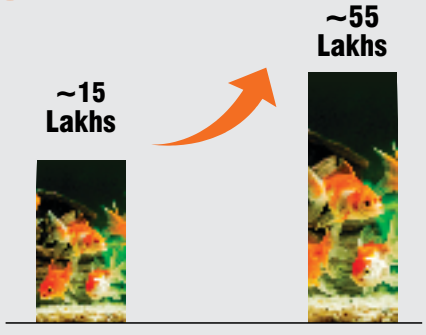

पर कैपिटा मत्स्य खपत

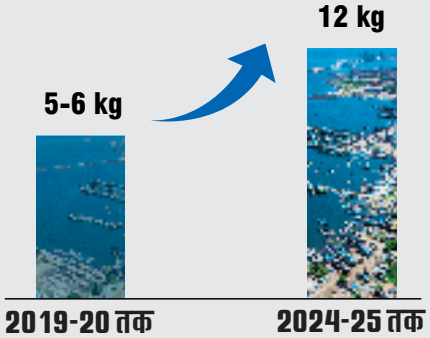

मात्स्यिकी निर्यात करोड़ में

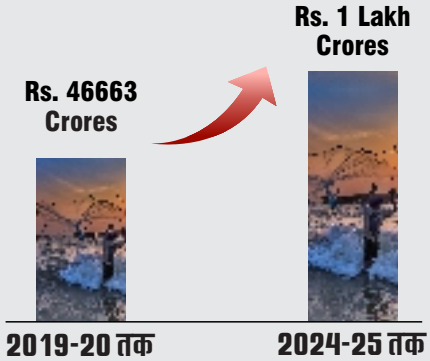

सफलता की कहानी

श्री मेदिसेट्टी वेंकटरमणआ, आंध्र प्रदेश

श्री मेदिसेट्टी वेंकटरमणआ ने वर्ष 2018–19 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एमएसआर एक्वा प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इसमें एक प्रयोगशाला सुविधा के साथ 2.20 एकड़ क्षेत्र में फैली एक हैचरी शामिल है। यह हैचरी देश में बहु प्रजाति समुद्री मत्स्य बीज उत्पादन के लिए एक मॉडल हैचरी के रूप में कार्य करती है। ऐसे निरंतर और समर्पित प्रयासों के साथ श्री मेदिसेट्टी वेंकटरमणआ आरएएस में विभिन्न समुद्री प्रजातियों का कल्चर शुरू करने और पूरे भारत में स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग की आपूर्ति करने के इच्छुक हैं।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश	नीली क्रांति योजना, 1.03 करोड़ रु/- विध्यमान श्रीम्प हेचेरी को मोडीफाई करने के लिए

परियोजना की मुख्य बातें

- सिल्वर पोम्पानो, इंडिया पोम्पानो, कोबिया और समुद्री बास प्रजातियाँ
- वार्षिक मत्स्य बीज उत्पादनरू 3–5 मिलियन हैचरी स्पान और फिंगरलिंग की आपूर्ति करती है और इसने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की हैचरी और नर्सरी पालन इकाइयों के साथ बहुत अच्छे मार्केट लिंकेज स्थापित किए हैं।
- 34 श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित

आय में वृद्धि

वार्षिक आय
4 करोड़

वित्तीय समावेशन

भारत सरकार ने मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी, केरल में चक्रवात प्रभावित मछुआरों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए

In FY2018-19, Government of India extended Kisan Credit Card (KCC) facility to fishers & fish farmers to help them meet their working capital and short-term credit needs

माननीय प्रधानमंत्री कर्नाटक में केसीसी प्रदान करते हुए

मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए कई वित्तीय समावेशन पहल शुरू की गई हैं।

2018-19 से 2023-24 तक की उपलब्धि

1.54 लाख
केसीसी मंजूर किए गए

मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के विकास पर फोकस

- मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है ।
- नीली क्रांति, एफआईडीएफ और पीएमएमएसवाई के तहत 107 मत्स्यन बंदरगाह और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों का विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

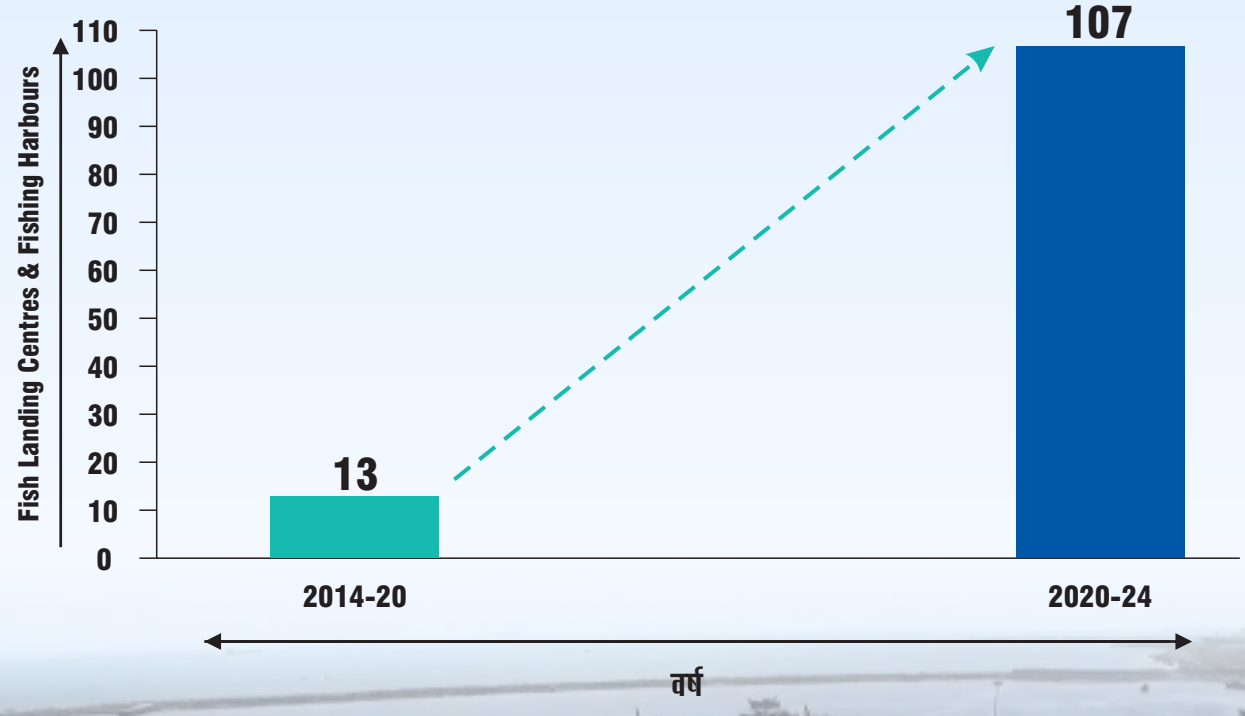

समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस)

मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसका पूरा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है।

5 लाख रु/-
आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए प्रदान किए जाते हैं

25 लाख रु/-
आकस्मिक स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए

25,000 रु/-
अस्पताल में भर्ती होने के लिए

2021–22 के दौरान **29.11 लाख** और 2023–24 के दौरान **33.86 लाख** मछुआरों ने नामांकन किया

वार्षिक मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता

सरकार मछुआरों और मत्स्य किसानों की आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए वार्षिक मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।

सहकारी समितियाँ और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ)

मत्स्य सहकारिताओं और एफएफपीओ में समूह दृष्टिकोण के प्रोत्साहन और उनकी बरगेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए सहकारिताएँ और मत्स्य किसान उत्पादक संघ (एफएफपीओ)

2195 एफएफपीओ
के गठन के लिए
कार्यान्वयन एजेंसियां एसएफएसी, नेफेड, एनएफडीबी एनसीडीसी और एफएफपीओ को
544.85 करोड़ रुपये

स्टार्ट अप ईको सिस्टम की सहायता एवं विकास

मात्स्यिकी क्षेत्र को एक शक्तिशाली आय और रोजगार उत्पादक के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यह कई सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है और स्टार्ट–अप और छोटे व्यवसायों के लिए कई अवसर प्रदान करता है।

डीपीआईआईटी ने
71
स्टार्ट-अप को

कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश
में सबसे ज्यादा मात्स्यिकी स्टार्ट-अप

मात्स्यिकी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का आयोजन मत्स्यपालन विभाग (जीओआई) द्वारा किया गया है जिसका उद्देश्य एक नवाचार कल्चर को बढ़ावा देना है।

- 121 स्टार्ट–अप आवेदन प्राप्त हुए
- 4 पूर्व–चिह्नित क्षेत्र के मुद्दों का समाधान प्रदान करने का लक्ष्य
- विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 विजेताओं का चयन और पुरस्कार प्राप्त नकद अनुदान प्राप्त हुआ
- शीर्ष 10 विजेताओं को अनुदान राशि और इंक्यूबेशन सहायता प्रदान की गई

मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्ट अप, एनएफएफडी 2023 में स्टॉल

पीएमएमएसवाई: 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान उपलब्धि (सितम्बर 2023 तक)

अंतर्देशीय और समुद्री मात्सियकी का विकास

20,403.47 हे	अंतर्देशीय जलकृषि के लिए तालाब क्षेत्र
1,370.86 हे	खारे पानी की जलीयकृषि के लिए तालाब क्षेत्र
766	मत्स्य और स्कैंपी हैचरी
10	खारे पानी की बड़ी और छोटी समुद्री फिन फिश हैचरियाँ

सजावटी मत्स्य पालन का विकास

2,130 सजावटी मत्स्य पालन इकाइयाँ

153 एकीकृत सजावटी मत्स्य पालन इकाइयाँ (प्रजनन एवं पालन)

ठंडे पानी की मात्सियकी का विकास

5,036
नई रेसवे यूनिट्स

2929.69 हे
नए तालाब क्षेत्र

58
री सर्क्युलेटरी एकूयाकल्चर सिस्टम (आरएएस) यूनिट्स

46
ट्राउट हेचेरियाँ

लॉजिस्टिक्स और इनफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट

27
जलाशय का एकीकृत विकास

22
आधुनिक एकीकृत फिश लैंडिंग सेंटेर्स

14
ब्रूड बैंक

मत्स्य बेचने और वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन

25,193
कुल मत्स्य परिवहन सुविधाएं

9,858
मोटर साइकल

9,282
आइस बॉक्स के साथ बाई साइकल

3,640
ऑटो रिक्शा

1,138
इनसुलेटेड ट्रक

294
रेफरीजेरेटेड ट्रक

भंडारण, उद्यम इकाइयों और बाजारों का विकास

सजावटी मत्स्य पालन के साथ मत्स्य किओस्क

6,542

937 फिश फीड मिल/प्लांट्स

1011 लाईव फिश वेंडिंग सेंटेर्स

563 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज

188 Fish retail market

9 स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल मार्केट

108 मूली संवर्धित उद्यम इकाईयां

एक्वाटिक हेल्थ मेनेजमेंट सिस्टम

स्वदेशी झींगा (इंडियन व्हाइट श्रीम्प्स) जलीय कृषि का विकास–पी. इंडिकस प्रजाति का आनुवंशिक सुधार **25.04 करोड़**

नेशनल सर्वेल्लेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डीसीस (एनएएसपीएडी) प्रोग्राम **41.09 करोड़ रु/-**

29 मोबाइल केंद्र और परीक्षण लैब

15 डीसीस डायाग्नोस्टिक सेंटर और क्वालिटी परीक्षण लैब

5 एक्वाटिक रेफेरील लैब

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य पालन का विकास

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में दूरस्थता और कठिन इलाके के कारण क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप किए जा रहे हैं

मध्यम बायोफ्लॉक इकाई
कामरूप जिला असम

मिनी फीड मिल
बिश्वनाथ जिला, असम

केज कल्चर
मिजोरम में सेरलुई बी बांध,

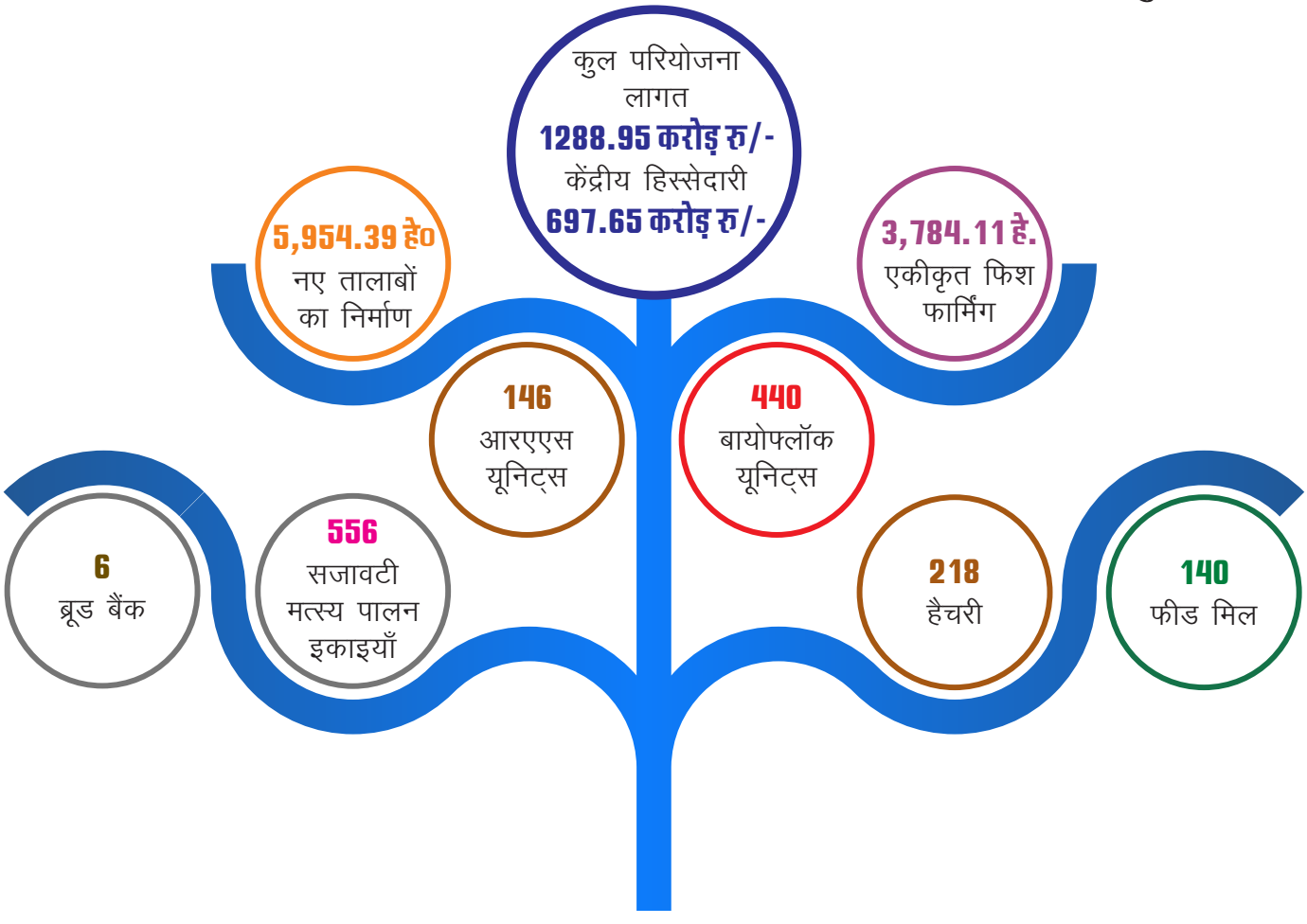

प्रशिक्षण जागरूकता और आउटरीच

1325
कार्यक्रम सम्पूर्ण

1,28,970
प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया

आउटरीच कार्यक्रमों में **3.00 करोड़** प्रतिभागियों को शामिल किया गया

मछुआरों का कल्याण

मत्स्यन पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान **6,77,462** मछुआरे परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता

6,468
नाव और जाल की रीप्लेसमेंट

एक्वापार्क का विकास

बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु – **127.71** करोड़ रुपये

संबलपुर, ओडिशा में एकीकृत इक्वापार्क– **100.00** करोड़ रु.

निजामपट्टनम, आंध्र प्रदेश में एकीकृत इक्वापार्क– **88.08** करोड़ रु/–

उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में एकीकृत एक्वा पार्क– **44.50** करोड़ रु/–

जीरो, अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत इक्वापार्क– **43.59** करोड़ रु/–

क्षमता निर्माण और विस्तार सेवाएँ

2,494
सागर मित्र

79
मत्स्य सेवा केन्द्र

गडवासु, लुधियाना में गहन जलकृषि प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता निर्माण संसाधन केंद्र

- 1.39 करोड़ के कुल निवेश के साथ प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और नवीन अनुसंधान एवं विकास के लिए संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं और जलवायु और पानी की बचत के अनुसार आरएएस, बायोफ्लॉक्स आधारित प्रणालियों जैसी गहन जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना है।

सफलता की कहानी

श्री मोहम्मद इलियास अहमद, लद्दाख

श्री मोहम्मद इलियास अहमद ने सरकारी या निजी नौकरी करने के बजाय मात्स्यिकी का विकल्प चुना। अपनी वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए, मात्स्यिकी के लिए लद्दाख में प्रतिकूल कठोर ठंडी जलवायु परिस्थितियों के बावजूद, उन्होंने ट्राउट की खेती में निवेश किया। उन्होंने योजना से प्राप्त सहायता से एक रेसवे का निर्माण किया, 300 रेनबो ट्राउट फिंगरलिंग का भंडारण किया।

ट्राउट फार्मिंग ने उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बढ़ाया है और नियमित आय सुनिश्चित की है। वे एक अतिरिक्त रेसवे का निर्माण करके अपनी इकाई का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। वे रोजगार प्रदान करते हैं और बेरोजगार युवाओं को मात्स्यिकी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन देकर उनकी सहायता करते हैं।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
कारगिल, लद्दाख	नीली क्रांति योजना, 2017–18, रेसवेज में ट्राउट कल्चर के लिए 3.50 लाख रुपए

परियोजना विशेषताएँ

- रेनबो ट्राउट रेयरिंग
- वार्षिक मत्स्य उत्पादनः 1.12 टन
- 2 श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित

बढ़ी हुई आय

सालाना टर्नओवर **4.28 करोड़ रुपए**

नई पहल

तटीय राज्यों में आर्टिफिशियल रीफ्स की स्थापना

आर्टिफिशियल रीफ्स मानव निर्मित या प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिन्हें मत्स्य भंडार को पुनः भरने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बढ़ाने और समुद्री मात्स्यिकी में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चयनित क्षेत्रों में रखा जाता है। सी अथवा ओशियन रैंचिंग के साथ–साथ आर्टिफिशियल रीफ्स की स्थापना से अधिक फिश कैच सुनिश्चित होती है और मछुआरों के लिए आजीविका में सुधार होता है।

संख्या 732
कुल निवेश
228 करोड़ रुपये

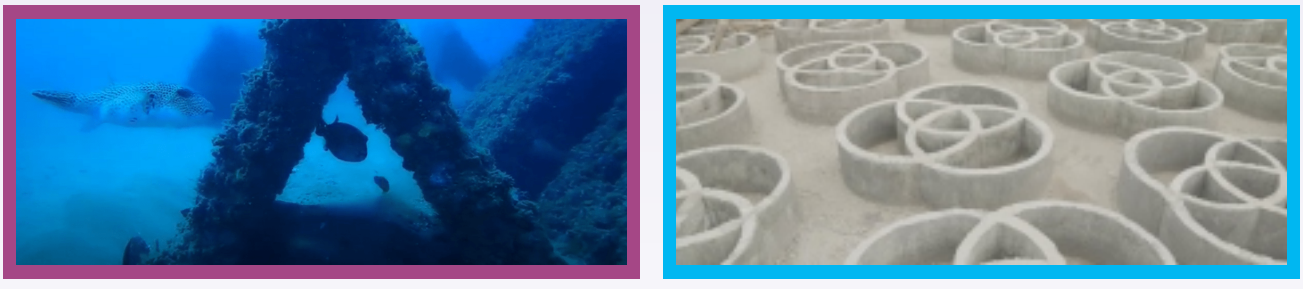

आर्टिफिशियल रिफ्स का विकास, आंध्र प्रदेश

समुद्री मत्स्यन जहाजों पर पोत संचार और सहायता प्रणाली

समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लाख मत्स्यन जहाजों पर उपग्रह–आधारित वेसल संचार और सहायता प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे वे अपने परिवारों के साथ जुड़े रह सकें और चक्रवातों और तूफानों के दौरान या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास मत्स्यन के दौरान सहायता प्राप्त कर सकें।

MAKE IN INDIA

इसरो, अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित

संचार और सहायता प्रणाली वाला जहाज, तमिलनाडु

फेज़ चेंज मेटीरियल

फेज चेंज मेटेरियल (पीसीएम) एक मेटेरियल इनोवेशन है जिसमें इंसुलेटेड फिश बॉक्स होते हैं। इससे मत्स्य की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, मत्स्य की पोर्टेबिलिटी और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही ऊर्जा की खपत भी कम होती है। पीसीएम के साथ बक्सों में हार्वेस्ट और भंडारण किए गए मत्स्य ताजा और स्वच्छ रूप में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है।

पाइलट: 50,000
कुल लक्ष्य: 1.5 लाख

पीसीएम केसेट्टस के साथ इंसुलेटेड आईस बॉक्स

जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए आउटबोर्ड इंजन नौकाओं के लिए हरित ईंधन (एलपीजी) का उपयोग

अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप मोटर चालित मत्स्यन जहाजों में स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। मेसर्स सूर्या मरीन्स द्वारा सिफनेट और मत्स्यफेड, केरल के सहयोग से किए गए पायलट परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकला कि एलपीजी किट पेट्रोल और केरोसिन आधारित मोटर इंजनों को बदलने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनकी चलने की लागत कम है, पर्यावरणीय प्रभाव कम है, आंतरिक भागों की कम टूट–फूट आदि के कारण लंबा जीवन है।

पाइलट: 20,000
कुल लक्ष्य: 1.2 लाख

एलपीजी किट के लिए परियोजना परीक्षण, केरल

सागर परिक्रमा यात्रा

माननीय केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के नेतृत्व में सागर परिक्रमा यात्रा नाम से एक विशिष्ट मछुआरा आउटरीच कार्यक्रम मार्च 2022 से गुजरात से पश्चिम बंगाल तक एक पूर्व–निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भारत की लगभग 8000 किलोमीटर की तटरेखा को कवर करना है।

उद्देश्य

- समुद्री मात्स्यिकी की स्थिरता को बढ़ावा देना
- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना
- तटीय क्षेत्र में समुद्री मछुआरों तक पहुँचने के लिए सामूहिक प्रयास
- मछुआरों के मुद्दों को उनके घर–द्वार पर संबोधित करना

सागर परिक्रमा के अंतर्गत कवर किए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिन्हें कवर किया जाना है

मार्च 2022 से सितम्बर 2023 तक का सफर

6374 कि.मी. कवर किया गया	9 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	87 स्थान	71.20 लाख लोगों तक पहुंचा गया

RuPay

Launches

सफलता की कहानी

श्री जोधन प्रसाद, झारखण्ड

श्री जोधन प्रसाद ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक छोटे से तालाब में मत्स्य पालना शुरू किया जिससे उन्हें 32000 रुपये प्रति माह कमाने में मदद मिली। इस निरंतर आय ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया लेकिन उन्हें बीमारी के प्रकोप और पूंजी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसके बाद वे केज कल्चर की प्रणाली अपनाने लगे ।

स्थान	योजना से प्राप्त लाभ
हजारीबाघ झारखंड	नीली क्रांति योजना, 2016-17, दो केजों की एक केज बेट्टरी स्थापित करने के लिए 2.7 लाख रुः

परियोजना की मुख्य बातें

- जमुनिया जलाशय में केज उत्पादन क्षमता 12 टन
- वार्षिक मत्स्य उत्पादन 8 टन
- पंगेशियस रियरिंग
- 90 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ
- अस्थायी बीज भंडारण और वातन सुविधा के साथ लाईव मत्स्य बिक्री केंद्र के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इलेक्ट्रॉनिक वजन करने की मशीन, जीवित मत्स्य परिवहन सुविधा आदि

सर्वोत्तम जलकृषि पद्धतियों को अपनाया गया

- केज के जाल की नियमित सफाई और उपचार
- बेहतर जल विनिमय के लिए नियमित अंतराल पर केजों को शिफ्ट करना
- सर्दियों के मौसम में प्रत्येक केज में चूने की थैली लटकाकर चूने का प्रयोग, आहार प्रबंधन और समय पर हार्वेस्ट

शुरू की गई औटरीच गतिविधियां

मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, विभागों के स्वायत्त और अधीनस्थ संस्थानों के सहयोग से आउटरीच गतिविधियां शुरू की गई हैं।

2020-21 से ~ 3.00 करोड़ हितधारकों तक पहुंच हासिल हुई

मत्स्यपालन विभाग द्वारा व्यापक आउटरीच और जागरूकता सृजन

निफेट, कोच्चि द्वारा समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन पर 3–दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण

भारतीय डेयरी उद्योग और तकनीकी एक्सपो, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

Dr. Abhilaksh Likhi, Secretary DoF, visited the DoF office he inspected the cleanliness drive and gave his feedback.

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर जनसंचार

रिपोर्ट फिश डिजिज ऐप का लॉन्च कार्यक्रम

कॉफी टेबल बुक का विमोचन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में मीठे पानी में मत्स्यपालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीएमएमएसवाई की दूसरी वर्षगाँठ के दौरान पुस्तिकाओं का विमोचन

पीएमएमएसवाई की तीसरी वर्षगांठ का जश्न

IN NEWS

PM launches Matsya Sampada Yojana, says scheme will double fish exports in 3-4 years

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, PATNA,
SEPTEMBER 10

PRIME MINISTER Narendra Modi on Thursday launched the PM Matsya Sampada Yojana, which aims to double fish exports in three-four years.

Launching the scheme via video-conference, the PM said, "Today the scheme is being launched in 21 states across the country. Over Rs 20,000 crore will be spent on this in the next 4-5 years. Works worth Rs 1,700 crore are being started today. Under the scheme, several facilities have been inaugurated in Patna, Purnia, Sitamarhi, Madhepura, Kishanganj and Samastipur."

This is the first such comprehensive plan to promote fisheries in the country, he said, adding, "The goal is to double fish exports in the coming 3-4 years."

PM Narendra Modi at the launch of the scheme. *PTI*

After opening his speech in Bhojpuri, Modi switched to Hindi to say: "The thinking behind launching sundry schemes today is to ensure that our villages should become India of 21st century and the strength of Atmnirbhar Bharat."

Bihar Chief Minister Nitish Kumar, Deputy Chief Minister Sushil Modi and Union minister Giriraj Singh joined the launch programme from Patna via video-conference.

Under the new scheme, fish producers will get new infrastructure, modern equipment, and new markets will be provided, Modi said. "This will increase earning opportunities through farming as well as other means." The scheme will boost fish, milk and honey production, paving the way for blue, white and sweet revolutions, he said.

The PM also launched other initiatives for fisheries, dairy and animal husbandry including e-GOPALA app, which will provide information "related to cattle care, from productivity to its health and diet". The app will enable cattle owners to buy and sell animals, said a statement from the government.

The PM said the Centre was looking at taking IVF technique in rearing calves to every village. "A cow generally gives birth to one calf in a year, but there have been experiments in laboratories getting several calves in a year through IVF technique. We intend to extend this technique to every village."

Referring to Mission Dolphin, which was announced on August 15, Modi said, "I learnt that Nitish Babu has been quite excited with the project. I believe if the number of dolphins goes up, it would benefit people living by Ganga." He was referring to the positive impact of rearing dolphins on fishery.

Lauding the work done by the Bihar government, Modi praised Nitish for the scheme to deliver drinking water to every home. "Till four-five years ago, only 2 per cent people were linked to supplied drinking water. This figure has now gone up to 70 per cent and about 1.5 crore households are linked to the scheme," he said.

Fisheries sector is key for growth of country's GDP, says Union Minister

Andhra Pradesh with its long coastline has enormous opportunities for the development of the sector, feels Kiren Rijiju

The Hindu Bureau
VIJAYAWADA

Union Minister for Earth Sciences Kiren Rijiju said that the fisheries and aquaculture sector is going to play a key role in the growth of the country's Gross Domestic Product (GDP).

He said there are enormous opportunities for the development of the fisheries sector in Andhra Pradesh which has a long coastline.

Mr. Kiren Rijiju was speaking at the Mega Awareness Campaign on Ocean Information and Advisory Services organised by Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), Hyderabad in collaboration with M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) at Machilipatnam of Krishna district on Friday. It was the first of the five campaigns planned by INCOIS on the western and eastern coasts of the country under the Azadi Ka Amrit programme.

Kiren Rijiju handing over devices for receiving information, to fishermen at Machilipatnam in Krishna district on Friday.

Mr. Kiren Rijiju said that India's enormous coastline helps the fisheries sector which is a top sector that contributes to India's GDP. Keeping this in mind Prime Minister Narendra Modi set a direction for development of India by 2047.

He further said that INCOIS has been disseminating key information such as ideal locations for fishing using indigenously developed technology to fishermen and boat owners who venture into the sea, which will help save a lot of fuel, manpower and time.

Minister for Housing Jogi Ramesh said the A.P. government is giving ₹10,000 financial aid to fishermen during the four-month fishing holiday. The State government is building eight fishing harbours in the State.

Machilipatnam MP Vallabhaneni Balashowry requested the Minister to set up a regional research institute for the fisheries sector in Machilipatnam.

Later, Mr. Kiren Rijiju distributed GEMINI devices, a portable receiver that can receive warnings, alerts and fishing locations, to fishermen and boat owners.

MSSRF executive director G.N. Hariharan, INCOIS director T. Srinivas Kumar, Earth Sciences Ministry Joint Director Senthil Pandian, and Krishna Collector P. Raja Babu were present.

IN NEWS

दैनिक भास्कर बालोद-दल्ली 10-07-2023

मछली पालन से प्रदेश के 2.21 लाख किसानों को मिल रहा रोजगार

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस आज: तांदुला, गोंदली सहित प्रदेश के 25 जलाशयों में पांच हजार केज लगाने का काम पूरा, दस हजार और लगाने की योजना

भास्कर न्यूज | बालोद

सोमवार को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। इस मत्स्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 2 लाख 21 हजार किसान मछली पालन कर रहे हैं। जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। वहीं प्रदेश के 25 जलाशयों में 5 हजार केज लगाने का काम पूरा हो चुका है। जिले के तांदुला, गंगरेल, गोंदली सहित प्रदेश के कुल 25 बांधों में मछली पालन के जरिए 50 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। इस को ये राष्ट्रीय अवॉर्ड मिलने के बाद मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है।

प्रदेश के 25 जलाशयों में अब तक 39035.75 हेक्टेयर जलक्षेत्र में केज लगाने का काम पूरा हो चुका है। तांदुला, खरखरा व गोंदली जलाशय में मछली पालन हो रहा है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी प्लानिंग अनुसार केज लगा है। इसके लिए केंद्र व राज्य शासन से अनुमति दी है। मछली पालन विभाग रायपुर के सहायक संचालक एमके साहू ने बताया कि पंगेसियस व तिलापिया जैसे मछलियों का पालन एवं जलाशयों में केज कल्चर कर सीमित पानी में अधिक मछलियों के उत्पादन के लिए प्लानिंग बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेशभर के अधिकतर जलाशयों में चार हजार से ज्यादा केज लगे हैं। जहां मछली पालन हो रहा है। भविष्य में 10 हजार केज लगाने की प्लानिंग बनी हुई है।

बालोद. मछली पालन के लिए तुलसा जलाशय में केज लगाया गया है।

मछली बीज उत्पादन में पांचवें, पालन में 6वें नंबर पर हम: मछली पालन विभाग रायपुर के अनुसार फिलहाल की स्थिति में देश के टॉप-10 प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां मछलीपालन हो रहा है। वर्तमान में हम देशभर में 6वें नंबर पर है। जबकि बीज उत्पादन में 5वें नंबर पर है। एक केज लगाने में लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए है। एक केज में 3000 से 3500 वहां तैयार मछलियां होंगी।

जानिए, किन जलाशयों के कितने क्षेत्र में मछली पालन

जलाशय	जलक्षेत्र हे.
दुधावा कांकेर	2541
माड़मसिल्ली धमतरी	1367
सिकासेर गरियाबंद	1174
[illegible]	2518
कोडार महासमुंद	2050
खरखरा बालोद	1875
तांदुला बालोद	2275
गोंदली बालोद	1118
दर्री कोरबा	1333.75
खुड़िया मुंगेली	1667
खूंटाघाट बिलासपुर	2712
हसदेव बांगो कोरबा	11500
गंगरेल धमतरी	6915
योग	39035.75

(मछली पालन विभाग रायपुर के अनुसार)

हिन्दुस्तान

गंगा नदी में छोड़े गए मछलियों के दो लाख बीज

पहल

- सिफरी की ओर से कोटवा नारायणपुर घाट पर हुआ कार्यक्रम
- विलुप्त हो रही मत्स्य प्रजातियों को बचाने की कवायद

बलिया, संवाददाता। गंगा नदी में विलुप्त हो रहे मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय अंतर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) की ओर से शनिवार को कोटवा-नारायणपुर घाट पर गंगा नदी में दो लाख भारतीय प्रमुख कार्प का बीज छोड़ा गया। राष्ट्रीय नदी रैंचिंग कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि सांसद वीरेन्द्र सिंह मस्त की मौजूदगी में कतला, रोहू व मृगल मछलियों के बीज का संचय किया गया।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉ. बीके दास ने गंगा नदी में मछली व रैंचिंग के महत्व को बताया। कहा कि इस वर्ष गंगा नदी में कम हो रहे महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के 25 लाख से ज्यादा बीज का रैंचिंग किया गया है।

नरही क्षेत्र के कोटवा- नारायणपुर में शनिवार को मछली के बीजों को गंगा में छोड़ते सिफरी के सदस्य ।

मुख्य अतिथि ने पतितपावनी गंगा को स्वच्छ रखने तथा जैव विविधता को बचाने का आह्वान किया। जिले के जलभराव वाले क्षेत्र सुरहताल, भागड़ नाला, मगही नदी, कोरहरा नाला आदि में भी मत्स्य उत्पादन के लिए प्रेरित किया। कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा जल क्षेत्रों के प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। सांसद ने मत्स्य पालन के साथ मिश्रित कृषि व मोटे अनाज की खेती को अपनाने की भी अपील की।

इस दौरान सांसद ने सक्रिय व जरूरतमंद मछुआरों को जाल भी वितरित किया। बीडीओ शिवांकित वर्मा, मत्स्य निदेशक संजय कुमार, जिला कृषि अधिकारी डीके सिंह आदि ने जैव विविधता व मछलियों के बारे में लोगों को जागरूक किया।

केंद्र प्रभारी डॉ धर्मनाथ झा ने संचालन किया, जबकि संस्थान के वैज्ञानिक डॉ राजू बैठा ने सबका आभार जताया। वैज्ञानिक डॉ मिलेश रामटेक, डॉ विकास आदि की अहम भूमिका रही।

IN NEWS

कलेक्टर सिन्हा ने थपथपाई पीठ, मछलीपालन करेंगे नौजवान तो तरक्की पक्की

इंजीनियर सत्येन्द्र बने फैमस फिसरीमैन खेती कर कमा रहे लाखों का मुनाफा

नवभारत ब्यूरो । जांजगीर-चांपा।

भला ऐसा कौन होगा जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मछलीपालन के कार्य को अपना कॅरियर बनाएगा, लेकिन एक ऐसे शख्स बलौदा विकासखण्ड के ग्राम ठड़गाबहरा में रहते हैं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ा और बताया कि बेहतर पढ़ाई करने के बाद भी व्यावसायिक क्षेत्र में कुशलता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, उन युवाओं के प्रेरणास्रोत गांव में रहते हुए मिसाल दे रहे हैं और गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में फैमस फिसरीमैन बनकर उभरे हैं। जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने उनके किये जा रहे कार्य को विगत दिनों जाकर करीब से देखा और कार्य की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई थी। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बलौदा नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 ठड़गाबहरा में सिविल इंजीनियर पास सत्येन्द्र प्रताप सिंह पिता महेन्द्र पाल सिंह जो आज मछली पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सत्येन्द्र इतने फैमस पहले नहीं थे, वे बताते हैं कि सफलता उन्हें एक दिन में नहीं मिली बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत की तब

जाकर परिणाम सामने आया है। परिवार की इच्छा थी कि सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद सरकारी या किसी बड़ी कंपनी में प्राइवेट नौकरी करूं, इसके लिए जमकर तैयारी भी की, लेकिन इसी बीच कोरोना का वह दौर आया जिसने नौकरी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। नौकरी लगना तो दूर जिनके पास नौकरी थी उनको भी घर पर बैठना पड़ा, इसी बीच बड़े भाई ने मछलीपालन के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से मछलीपालन का कार्य शुरू किया। जिसमें मछली पालन विभाग से सतत रूप से तकनीकी मार्गदर्शन मिलता रहा साथ ही मछलीपालन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से भी मार्गदर्शन लिया। वे बताते हैं कि मछली पालन के लिए पहले 2 बायो फ्लॉक बनाए गए, एक-एक टैंक 6 लाख लीटर पानी स्टोरेज का जिसमें 12 लाख रूपए की राशि का खर्चा आया।

कलेक्टर ने कहा युवा आगे आएं तो बदल सकते हैं किस्मत

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा विगत दिनों बलौदा विकासखण्ड के दौरे पर थे, उस समय उन्हें अधिकारियों ने सत्येन्द्र द्वारा किये जा रहे मछली पालन कार्य के बारे में जानकारी दी। कलेक्टर श्री सिन्हा ने युवा सत्येन्द्र द्वारा किये जा रहे इस कार्य को करीब से देखने की इच्छा हुई। बायो फ्लॉक में किये जा रहे मछलीपालन कार्य को देखकर सत्येन्द्र की पीठ थपथपाई और कहा कि आप जैसे युवा जिले ही नहीं बल्कि राज्य के लिए भी मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने सत्येन्द्र से कहा कि वे इस कार्य को गौठान में बनाए जा रहे ग्रामीण औद्योगिक पार्क में कर सकते हैं और दूसरे युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.ज्योति पटेल ने भी सत्येन्द्र द्वारा कराए जा रहे कार्य की सराहना की और रीपा योजना से जुड़कर आगे बढ़ने कहा।

IN NEWS

हिन्दुस्तान

epaper हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान www.livehindustan.com **अपना सहरसा**

खत्म हो रही जंगली मछलियों के संरक्षण में जुटा मत्स्य विभाग

एक्सक्लूसिव

■ विजय झा

15 जून से 15 सितंबर तक मछली पकड़ने पर रोक

■ मछली पकड़ने वाले मल्लाहों को तीन महीने तक मिलेगा 15 सौ रुपये

■ 5 सौ परिवारों को दिया जा रहा लाभ, राष्ट्रीय बचत योजना के तहत योजना लागू

जून से सितंबर तक होता है प्रजनन काम

पूर्व में इस क्षेत्र में जंगली मछलियों की थी भरमार

योजना पर क्या कहते हैं पदाधिकारी

स्थानीय लोग लगातार कर रहे थे मांग

मछली बचाने का क्या है विभाग की योजना

जलीय जीवों की ऐप से होगी निगरानी

● केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रूपाला ने लॉन्च किया 'रिपोर्ट फिश डिजीज' ऐप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बुधवार को कृषि भवन में 'रिपोर्ट फिश डिजीज' मोबाइल आधारित ऐप लॉन्च किया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी मौजूद थे। ऐप को जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। इस ऐप को आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप मछली किसानों, क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर ले आएगा।

इस अवसर पर जेएन स्वैन, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डॉ. अभिलक्ष लिखी, ओएसडी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव, डीएआरई एवं महानिदेशक, आईसीएआर नई दिल्ली भी मौजूद थे। रूपाला ने कहा कि देश में 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों और मूल्य श्रृंखला में लगे कई लाख मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता प्रदान करता है। यह वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8 फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है।

IN NEWS

scampi fisheries will improve livelihoods of tribals

RAVIKANT MISHRA

SIMDEGA: A flagship project on Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement in reservoirs of Jharkhand has been launched with the stocking of 4.0 lakh scampi seeds in Kelagagh reservoir today. Four Fisheries Cooperative Societies (FCS) have been functional in this 162 ha reservoir with water level nearing to full reservoir level (FRL), members and secretaries of which remained present on site stocking of scampies with pre loaded hideouts for the released seeds to evade predatory pressure.

The stocking program was inaugurated by Smt Kusumlata, ADF, Dept of Fisheries, Simdega by releasing scampi seeds in the reservoir along with other Departmental officials of Jharkhand in presence Dr. A K Das, Principal Scientist & Project Principal Investigator of ICAR-CIFRI, the project executing organisation under able leadership of Dr B. K Das, Director of the Institute. The fish seeds from the numbers of fish packets have been randomly sampled and counted by the FCS members so as to know the exact number of live scampi seeds introduced into this reservoir. Feed and mineral nutrients have also been distributed to the four FCS enabling them to feed the stocked seeds properly for ensuring good growth and survival of the seeds. Smt Kusumlata, ADF has expressed her satisfaction over the whole procedures of stocking scampi in this reservoir which would benefit the fishers of this ecosystem both financially and nutritionally in the days to come. The project is the first of its kind in India being functional in three reservoirs, each of Gumla, Simdega and Hazaribagh district respectively.

जनपद में हुआ फिश सीड रैंचिंग प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन

राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर केंद्रीय मंत्री ने किया वर्चुवली उद्घाटन

उत्तरकाशी। मत्स्य विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को गंगोरी मत्स्य फार्म में मत्स्य पालकों के साथ राष्ट्रीय मत्स्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार एवं ब्लाक प्रमुख शैलेन्द्र कोहली सहायक निदेशक मत्स्य वृषी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत चेन्नई से देशभर के 176 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके साथ ही जनपद में भी फिश सीड रैंचिंग प्रोग्राम का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि मत्स्य पालन स्वरोजगार का अच्छा साधन है। उन्होंने सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देशित किया कि जनपद में मत्स्य पालन के इच्छुक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मत्स्य पालकों को निशुल्क मत्स्य बीज वितरित किए। तथा गंगा नदी में भी मत्स्य बीज का संचय किया गया।

IN NEWS

दैनिक जागरण हल्द्वानी, 11 जुलाई, 2023

पिथौरागढ़/चंपावत जागरण

रागढ़ के ललित
ल सिविल सर्विसेज
के लिए चयनित

पिथौरागढ़ के मत्स्य पालकों ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री से किया सीधा संवाद

उत्तराखंड में एकमात्र पिथौरागढ़ जनपद को मिला **वर्चुअल कार्यक्रम** में शामिल होने का अवसर

पिथौरागढ़ में मत्स्य दिवस के अवसर पर फिश कियोस्क का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा (मध्य) ने सोमवार को किया • जागरण

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर जिले के मत्स्य पालकों को केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से संवाद का अवसर मिला।

उत्तराखंड में एकमात्र पिथौरागढ़ जनपद के मत्स्य पालकों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। वर्चुअल संवाद में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने सीमांत जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया। मत्स्य पालन दिवस पर जिला मुख्यालय के एक बैंक में वर्चुअल गोष्ठी का आयोजन हुआ। जिले के मत्स्य पालकों ने केंद्रीय मंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए और व्यवसाय में आने वाली दिक्कतें भी उनके सामने रखीं। वर्चुअल गोष्ठी में प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, मत्स्य पालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने पिथौरागढ़ जिले में तेजी से बढ़ रहे मत्स्य पालन की सराहना की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने जिला मुख्यालय में पहले फिश कियोस्क का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन विभाग के उपनिदेशक डा रमेश चलाल ने बताया कि कियोस्क मत्स्य पालक और उपभोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करेगा। उपभोक्ताओं की मांग पर मत्स्य पालकों से संपर्क कर ताजा मछलियां उपलब्ध कराने के साथ ही मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज, मछली पकड़ने के विभिन्न उपकरण, जाल, दवा आदि भी उपलब्ध कराएगा। जिले में यह पहला कियोस्क है। उत्पादकों को अब अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी [illegible] चौधरी, कैलाश भट्ट, मत्स्य पालक दीवान मेहता, राजेंद्र मेहता, हेमराज सिंह, दीपेंद्र सिंह, लक्ष्मी मेहता, रेखा भंडारी आदि मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क

मछली पालन से आर्थिक सशक्तीकरण

केज कल्चर | बांगो डुबान में केज कल्चर से मछली पालन, 800 परिवार के सदस्य लाभान्वित हो रहे

आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे मछुआरे

IN NEWS

दैनिक भास्कर

2023-10-04
पूर्णियाँ (-4)

भास्कर खास • विभिन्न योजनाओं व कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाए गए तालाब, एक सौ और बनेंगे

मछली उत्पादन का हब बनेगा सहरसा; तीन साल में 150 तालाब का हुआ निर्माण, सालाना 10 करोड़ का होगा कारोबार, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार

कंटहा गांव में तालाब से मछली निकालते किसान।

महिषी का कंटहा गांव बना मत्स्य ग्राम

मछली उत्पादन में जिला आत्मनिर्भर

IN NEWS

मत्स्यपालन विभाग
DEPARTMENT OF FISHERIES

NFDB

FOCUS
FISHERIES

EMPOWERING COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMEN THROUGH "Sagar Parikrama Yatra"

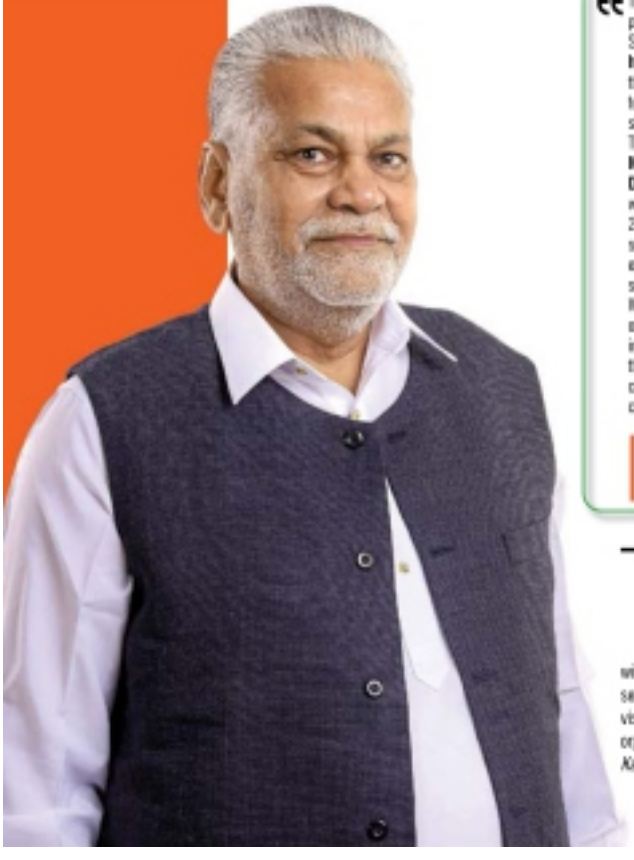

"The **success of the Sagar Parikrama Yatra** is a testament to the transformative power of visionary leadership. Under the able guidance of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, our government has been on a relentless pursuit towards **holistic development** of Maa Bharti's vast 8,000 km+ coastline, with a focus on the welfare of our fishermen community. The Sagar Parikrama Yatra being organized to express our gratitude to our three seas and our hardworking fishermen, is a shining example of the impact we can create through collective efforts.

Through initiatives like the **'Blue Revolution-Integrated Development and Management of Fisheries' Scheme, Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund** and the **Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)**, we have witnessed an impressive double digit growth in fish production during 2021-22, reaching an all-time high of 162.4 lakh tonnes in fish production. Similarly, our sea-food exports stood at record earning of Rs. 57,586 Cr. during 2021-22. I am extremely optimistic about the future of our fisheries, animal husbandry, and dairying sectors, as we continue to march forward on the path of progress and development. With initiatives like the PMMSY and the Kisan Credit Card (KCC), we are providing our farmers with the necessary resources and support they need to thrive. These initiatives are contributing to transformation of our economy and upliftment of the lives of millions of our fishers and fish farmers. As we move forward, we are committed to our vision of a self-reliant India, and are working tirelessly towards creating a better future for ourselves and for generations to come."

SHRI PARSHOTTAM RUPALA
Union Cabinet Minister of Fisheries,
Animal Husbandry and Dairying

The Indian Ocean is vital to the economies, security, and livelihoods of its coastal nations. With a vast coastline of 8,118 km covering 9 maritime states and 4 Union Territories in India, it provides livelihood support to millions of coastal communities especially our hardworking fishermen. The lives of these traditional fishermen are intertwined with oceans and seas since times immemorial. To express gratitude to our seas and fisher folk, Department of Fisheries, Government of India, under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Sh. Narendra Modi, successfully organizing the **"Sagar Parikrama Yatra"** as the nation celebrated 75th *Azadi Ka Amrit Mahotsava*.

“हमारी सरकार मत्स्य किसानों के जीवन में सुधार लाने पर बल देते हुए एक जीवंत मात्स्यिकी क्षेत्र की दिशा में काम करती रहेगी”

नरेन्द्र मोदी
प्रधान मंत्री

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार